ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 157-158
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

उच्च शिक्षण में भारतीय भाषाओं का विकास

सम्पत सिंह कोठारी

1. लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर : अमेरिकन पीस कोर, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, भारत
शोध अधिकारी : भाषा शिक्षण, साहित्य संस्थान, उदयपुर विद्यापीठ, उदयपुर (राजस्थान) भारत
भाषा शिक्षण : डॉ. एन्टोनियो, डॉ. सिल्वा, दादर (मुम्बई), डॉन बोस्को, किंग्स सर्कल (मुंबई) भारत
2. भूतपूर्व– प्रिंसिपल : प्रो. कोठारी एकेडमी (दो शाखाएँ), अंधेरी (पं.), गोरेगांव (पं.) मुम्बई (महाराष्ट्र)भारत
शोध सहायक : एडवान्स सेंटर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, डेक्कन कॉलेज, स्नातकोत्तर एवं शोध संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र), उप–सम्पादक, प्रदेश विकली, अपना देश, लंदन (यू.के)

Received-25.11.2023, Revised-01.12.2023, Accepted-06.12.2023 **E-mail: sampat-kothari@yahoo-co-uk**

सारांशः प्रस्तुत लेख में, उच्च शिक्षण में भारतीय भाषाओं की मौजूदा स्थिति पर एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। साथ ही साथ कुछ निर्धारणात्मक पक्षों पर मनन करने की कोशिश की गई है, जिससे कि भारतीय भाषाओं के विकास में एक नई दृष्टि कायम की जा सके ।

कुंजीभूत शब्द– विश्लेषणात्मक दृष्टि, साहित्यिक, सांस्कृतिक खजाना, विविध रूप–रंग, सामाजिक रचना, वैविध्यता, प्रान्तीय भाषाएँ।

१.१. प्रान्तीय भाषाओं के आधार पर भारत देश के विभाजन ने हमारी इन भाषाओं के विकास में एक नया आयाम कायम किया है। इन प्रान्तीय भाषाओं का अपना एक भरपूर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक खजाना है। इससे विविध रंगीय भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को विविध रूप–रंग प्रदान होते आया है। हमारे देश के विविध भाषीय एवं विविध सामाजिक रचना में हमें वैविध्यता एक सूत्र में बंधी हुयी प्रतीत होती है। रंगों भरी विविधता में भारत की एक आत्मा एवं भारतीय भाषाओं के एक संघटक रूप को हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। हमारे इस अमूल्य खजाने की सुरक्षा के लिए सभी मुमकिन कदम उठाने चाहिये। सभी प्रान्तीय भाषाएँ हमारे विकास एवं वैभव की चक्रयान हैं।

१.२. हमारे महान नेतागण एव सामाजिक वैचारक, हमारी भारतीय भाषाओं की प्रमुखता का दावा करते रहे हैं। उन्होंने इनके समुचित विकास की पूर्ण परिकल्पना की है।

"भारतीय मस्तिष्क का उच्चतम विकास अंग्रेजी भाषा के ज्ञान बिना संभव होना चाहिए।........ एक है। अंग्रेजी के मोह से मुक्त होना स्वराज के मूलभूत सिद्धान्तों में से एक है।"१ (महात्मा गॉधी, यंग इंडिया २–२–१९२१)

२.१. मौजूदा शिक्षण में अधिकतर विद्यार्थी उच्च माध्यमिक स्तर तक, हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी सहित किसी एक भारतीय भाषा में शिक्षण हासिल करते हैं। उच्च शिक्षण (यहाँ उच्च शिक्षण से तात्पर्य उच्च माध्यमिक के पश्चात् के शिक्षण से है) में जहाँ अधिकतर विद्यार्थी उन शैक्षणिक संस्थाओं से आते हैं, जहाँ कि शिक्षण का माध्यम किसी एक भारतीय भाषा में होता है और उस भाषा की कड़ी उच्च शिक्षण से जुड़ी हुई नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि कुछेक विश्वविद्यालयों को छोड़कर देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली अपनाई नहीं गई है। ऐसी स्थिति में हमारे विश्वविद्यालयों को अभी भी पूर्णतया अंग्रेजी पर आधारित रहना पड़ता है। यह व्यावहारिक तौर पर होते जाया है और हमारी युवा पीढ़ियां पिछले कई सालों से इस बात को सहन करते आ रही है। इस मामले पर हमारे कई जिला–शास्त्रियों ने कई बार कई मौकों पर विवाद किया है, लेकिन सभी व्यर्थ में और आज तक इस मामले का कोई उचित हल नहीं मिल सका है।

"प्रायः सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली के आधार पर स्कूल एवं उच्च शिक्षा का माध्यम अक्सर एक ही होना चाहिए। ....जैसा कि सही तौर पर हमने स्कूल स्तर तक प्रान्तीय भाषाओं का माध्यम रखा है, यह अनुसरण होता ही है कि हम उन्हें अधिक से अधिक तौर पर उच्च स्तर में अपनायें।"[१] (१. रिपोर्ट ऑफ द एज्यूकेशन कमीशन, अध्याय १, पृष्ठ १३।)

२.२. हमारे विश्वविद्यालयों एवं अन्य विशेष विभागों में अंग्रेजी के आधिपत्य ने भारतीय भाषाओं के उच्च शिक्षण में विकास को निष्फल कर दिया है। विशिष्ट वर्गीय एवं सामाजिक व अर्थशास्त्री समाज वर्ग से अंग्रेजी का एक किला कायम हुआ है। समाज के कुछेक सबिशेषाधिकारियों द्वारा बनाई हुई इस किले–बाजी को कई सदियों तक लोग सहन करते आये हैं, कर रहे हैं और कब तक हृदय करते रहेंगे। इसके बारे में, अगर सहनशीलता हमारे खून में घुस कर हमारे अभिलक्षण का एक अंग बन चुकी है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

"शैक्षणिक, प्रशासकीय एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अंग्रेजी के आधिपत्य ने, इन्हीं क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के विकास को पूर्णतया रोक दिया है यॉनि कि इन भाषाओं का, आधुनिक भाषा एवं आधुनिक विचारों की अभिव्यक्ति का वाहन बन कर विकसित रूप धारण करने से वंचित कर दिया गया है।"[२](२. एस. मोहन कुमारमंगलम् – इंडियाज् लैंग्वेज् क्राइसिस, पृष्ठ ६।)

२.३. राजनीति से उत्प्रेरित हिन्दी–विरोधी आन्दोलन ने इस देश में राष्ट्र भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी के प्रचार एवं हिन्दी के आधिपत्य (यदि इसे ऐसा उनकी भाषा में कहा जाए) का डटकर विरोध किया है। लेकिन इन्हीं लोगों को कभी भी विदेशी भाषा अंग्रेजी के आधिपत्य के विरोध में बोलते हुए नहीं देखा गया है जबकि अंग्रेजी भारतीय जनगणना १९६१ व १९७१ के अनुसार देश की संपूर्ण आबादी के लगभग ३ प्रतिशत (१९६१ की जनगणना के अनुसार २.८४:)[३] (३. इण्डियाज् लेग्वेंज क्राईसिस, पृष्ठ ८०।) लोगों की भाषा है और इन्हीं लगभग ३: आबादी वाले लोगों की अपनी एक मातृ–भाषा भी है जो कि भारतीय संविधान के आठवें नियत में सम्मिलित है।

२.४. कुछेक भारतीय विश्वविद्यालयों में जहाँ कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा वहाँ परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिये उनकी इच्छा पर है कि वे अपने उत्तर भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी में लिख सकते हैं, उनमें से अधिकतर विद्यार्थी इस सुविधा को नहीं अपनाते। इसका मुख्य कारण यही है कि आज भी हमारे युवक यह डर अपने दिल में रखते है कि बिना अंग्रेजी के लगाव के उनका भविष्य अंधकार में है और उन्हें यह महसूस होता है कि उनके नौकरी–धंधें के लिए अंग्रेजी की सर्वोपरिता जरूरी है।

२.५. उच्च शिक्षण में अधिकतर प्राध्यापक अपने विषय भारतीय भाषा के माध्यम से पढ़ाने में था तो सक्षम नहीं होते है या

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

अनिच्छित होते हैं।

२.६. अभी तक भारतीय भाषाओं में समुचित पुस्तकें एवं शैक्षणिक सांभग्रियाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ यह कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी कि इस तरह का कार्य सिर्फ अनुवादित सामग्रियाँ एवं शब्दावलियाँ पेश कर देने से पूरा नहीं होगा।

२.७. कई विषयों के विद्वान् एवं लेखक अभी भी अंग्रेजी का संमोह रखते हैं एवं अक्सर वे मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में नहीं लिखते हैं।

२.८. आजादी के बाद इस देश में आज तक संपूर्ण देश–स्तर पर हमारे शिक्षा–शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों एवं विद्यार्थियों ने मिलकर कभी भी इस तरह का आन्दोलन नहीं किया कि जो अंग्रेजी के स्थानान्तरण की मांग करता हो।

३.१. उच्च शिक्षण में भारतीय भाषाओं के विकास की मौजूदा समस्याओं एवं कमियों पर एक विस्तृत दृष्टि देने के पश्चात् इन उल्लेखित कमियों एवं रुकावटों से छुटकारा पाने के लिए सही दिशा में संभावित हल पाना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा यहाँ उल्लेखित मुद्दें भारतीय भाषाओं के विकास में काफी उपयोगी हो सकते हैं।

३.२. भारतीय विद्वानों एवं लेखकों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन एवं प्रलोभन देने चाहिये, जिससे कि वे मूलतः सभी विषयों में भारतीय भाषाओं में रचना कर सकें। ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय एवं प्रान्तीय वार्षिक पुरस्कार सभी विषयों में उनकी अनोखी रचनाओं के लिए दिये जाने चाहिए। यह बीड़ा क्रांतिकारक प्रेरणा से सही तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

३.२.१. इस दिशा में सभी प्रान्तों में पाठ्य–पुस्तक निर्माण ब्यूरो कुछ हद तक कार्य कर सके हैं लेकिन शिक्षा के एक प्रमुख क्षेत्र, उच्च शिक्षण के इस महान कार्य को संपूर्ण करने का बीड़ा अभी बहुत हद तक अधूरा ही है।

३.२.२. अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा भारत सरकार की मैसूर में स्थित भारतीय भाषाओं की केंद्रीय संस्था भी है, जो भारतीय भाषाओं के समुचित विकास का कार्य कर रही है। यह संस्था भाषा विज्ञान की विविध आधुनिक विधाओं से देश की भावुक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को कायम करने में फलीभूत हो रही है। लेकिन इस संस्था की दिशा भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षण में स्थान देने की ओर नहीं है। इस कार्य के लिए इस संस्था का सम्बन्ध अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं से होना अत्यन्त ही जरूरी है।

३.३. अगर केन्द्रीय एवं प्रान्तों की सरकारें जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी भाषाओं एवं अपना हिन्दी के उपयोग का प्रचार मजबूती के साथ करें तो अन्य क्षेत्र के लोगों को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी। इससे उच्च शिक्षण में अपनी मातृ–भाषा अथवा राष्ट्र भाषा में होमिन किया हुआ ज्ञान अपने ही देश में पूर्णतया उपयुक्त हो सकेगा। इससे जीवन के शैक्षणिक एवं व्यवहारिक इन दो पहलुओं में आपस में एक गहरा मौलिक सम्बन्ध कायम हो सकेगा।

३.४. अगर सभी राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता लोग यह ठान कार चलें कि वे अपना पूर्ण कारोवार राष्ट्र भाषा हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में कारें तो इससे एक मजबूत उदाहरण कायम होगा एवं इससे ज्यादा से ज्यादा लोग उत्साहित होकर इसका अनुसरण करेंगे।

३.५. सरकार को उन सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिये, जिससे कि मुफ्त में शहर व गांव के लोग भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम प्रदर्शनियों व दूरदर्शन केन्द्रों से देख सकें।

३.६. ''उर्दू सहित सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके उच्च–शिक्षण केन्द्र स्थापित होने अत्यन्त जरूरी है।''[१] (१. रिपोर्ट ऑफ द एज्यूकेशन कमिशन, पृष्ठ ६४६ ।)

४. हमारे देश के प्रजातंत्रीय सामाजिक विवा में, हमारे राष्ट्र की अमूल्य निधियों का जो कि चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक नैसगिक या शैक्षणिक क्यों न हों, उनके विकास का पूर्णतया स्याल रखना आवश्यक है, जिससे कि उनका अंश मात्र भी किसी वजह से दबाया न जाए और साथ ही साथ राष्ट्र की सभी तरह की संपूर्ण एकता सदैव बनी रहे। यह ध्यान में रखते हुए सभी संभव कोशिशें कायम रहें जिससे कि हमारी भारतीय भाषाओं को उनका प्रमुख स्थान प्राप्त हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

१. कुमार मंगलम्, एस्. मोहन : इण्डियाज् लैंग्वेज क्राइसिस, मद्रास–– दासगुप्ता, ज्योतिरिन्द्र भारत सरकार : न्यू सेन्चुरी बुक हाऊस, अध्याय २, ४, ५, १६६५।

२. लैंग्वेज कॉन्फलिक्ट एण्ड नेशनल डेवलपमेन्ट, ऑक्सफोर्ड युर्निव्हसिटी प्रेस, १६७०.

३. सेन्सस ऑफ इण्डिया, १६६१, वोल्युम १, पार्ट II. एज्यूकेशन कमीशन रिपोर्ट, १६६४–६६।

*****